POLSTRAT x TEAM CVOTER® we read the pulse of the nation

COVID-19 पोल

केवल 35.5% भारतीय सोचते हैं कि सरकार द्वारा प्रदान की गई कोरोनावायरस सहायता और राहत पूरी तरह से पर्याप्त है।

मई 2020 में किए गए **टीम C-voter** ने कोरोना ट्रैकर इकोनॉमी बैटरी (तरंग3) सर्वेक्षण में उत्तरदाताओं से कोरोनवायरस संकट के प्रभाव के बारे में उनके दृष्टिकोण और उनकी आर्थिक स्थिति पर लॉकडाउन के बारे में पूछा। सर्वेक्षण में लॉकडाउन के कार्यान्वयन पर उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण पर प्रश्न, सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज के साथ-साथ चिकित्सा देखभाल, भोजन और नौकरी के नुकसान को वहन करने में सक्षम नहीं होने का डर भी शामिल था।

कुल मिलाकर, जिस तरह से लॉकडाउन को लागू किया गया था, बहुसंख्यक उत्तरदाता लॉकडाउन के समर्थक थे। आज के इन्फोग्राफिक में, **टीम पोलस्ट्रैट** ने सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता और राहत पैकेजों पर उत्तरदाताओं के नजरिये का विश्लेषण

किया है।

Q क्या आप सरकार द्वारा लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और इसे लागू करने के तरीके का समर्थन करते हैं?

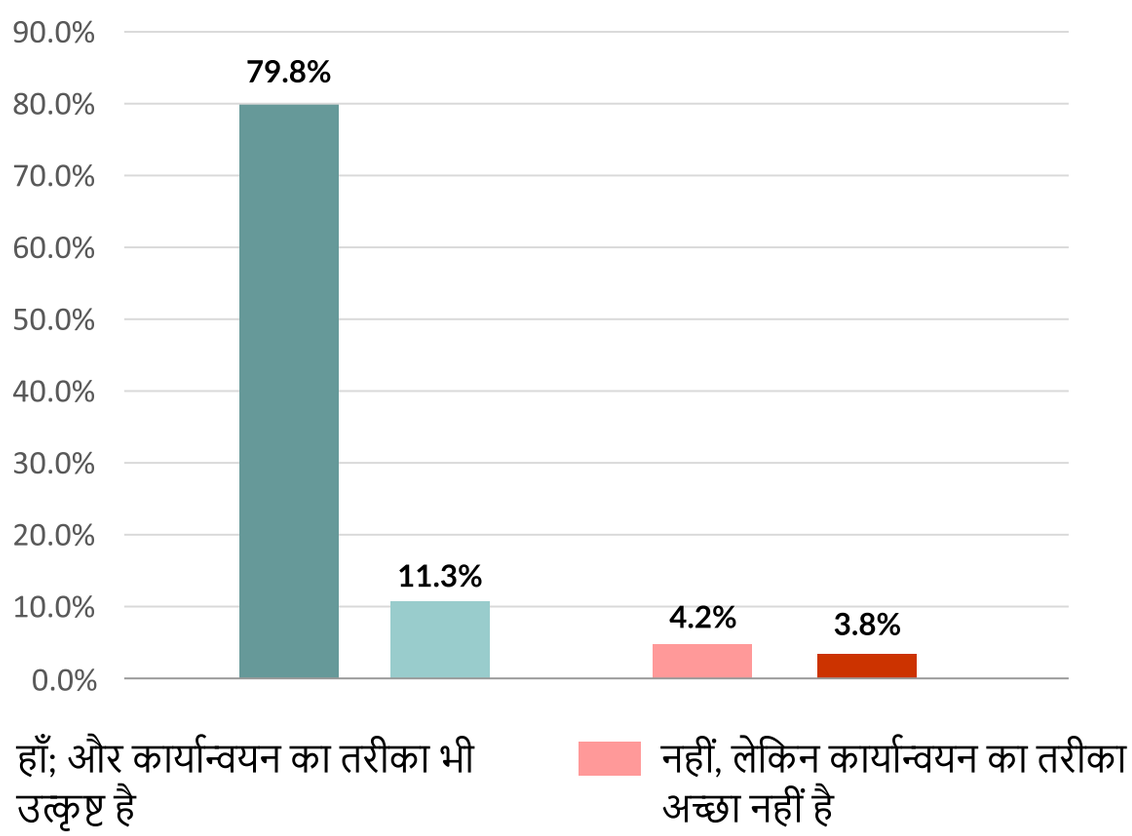

हाँ; लेकिन कार्यान्वयन का तरीका इतना अच्छा नहीं है

नहीं; और इसे लागू करने का तरीका भी खराब है

91.1%

कुल मिलाकर हाँ

8.0%

कुल मिलाकर नहीं

Q क्या आपको लगता है कि सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता पैकेज और राहत पर्याप्त है?

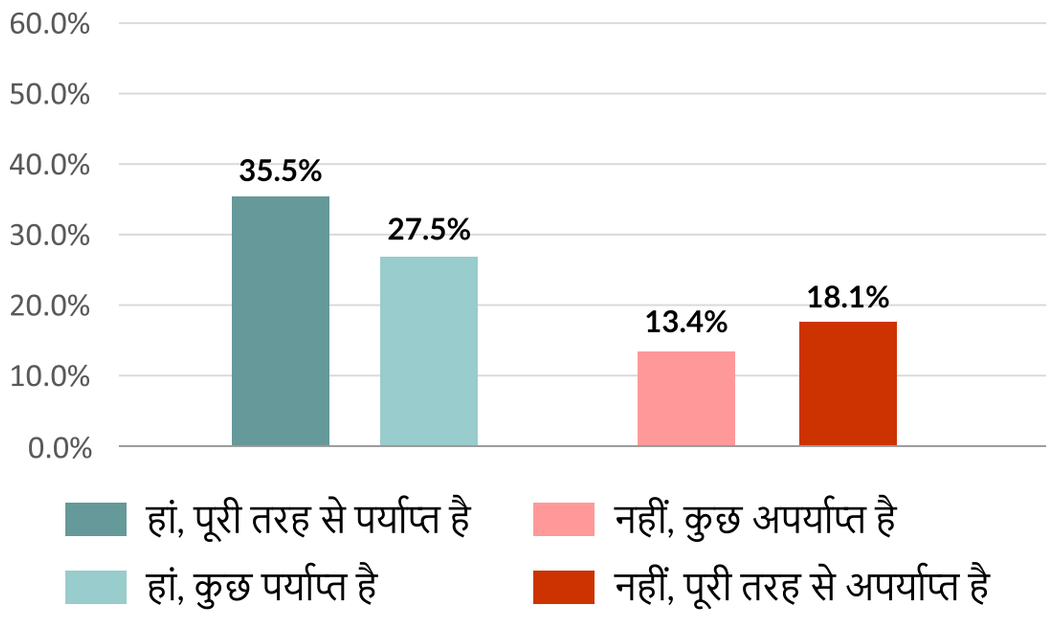

63.0%

कुल मिलाकर हाँ

31.5%

कुल मिलाकर नहीं

मुख्य निष्कर्ष

कुल मिलाकर, हमने पाया है कि **सरकार द्वारा लागू किए गए देशव्यापी बंद के लिए भारी समर्थन (91.1%) है**। वास्तव में, **79.8% उत्तरदाता लॉकडाउन और सरकार द्वारा** इसे **लागू करने के तरीके दोनों का समर्थन करते हैं**।

यह भारी समर्थन जनसांख्यिकी जैसे आयु समूहों, लिंग, आय और शिक्षा के अनुरूप है।

सरकार द्वारा **प्रदान किए गए राहत पैकेजों के लिए समर्थन मिला हुआ है, 35.5% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह पूरी तरह से पर्याप्त है।** कुल मिलाकर **63% को लगता है कि सरकारी राहत पर्याप्त थी, जबकि 31.5% को लगता है कि यह नहीं था।**

कौन सोचता है कि सरकारी सहायता और राहत का वादा किया जाना पर्याप्त है?

क्या आपको लगता है कि सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता पैकेज और राहत पर्याप्त है?

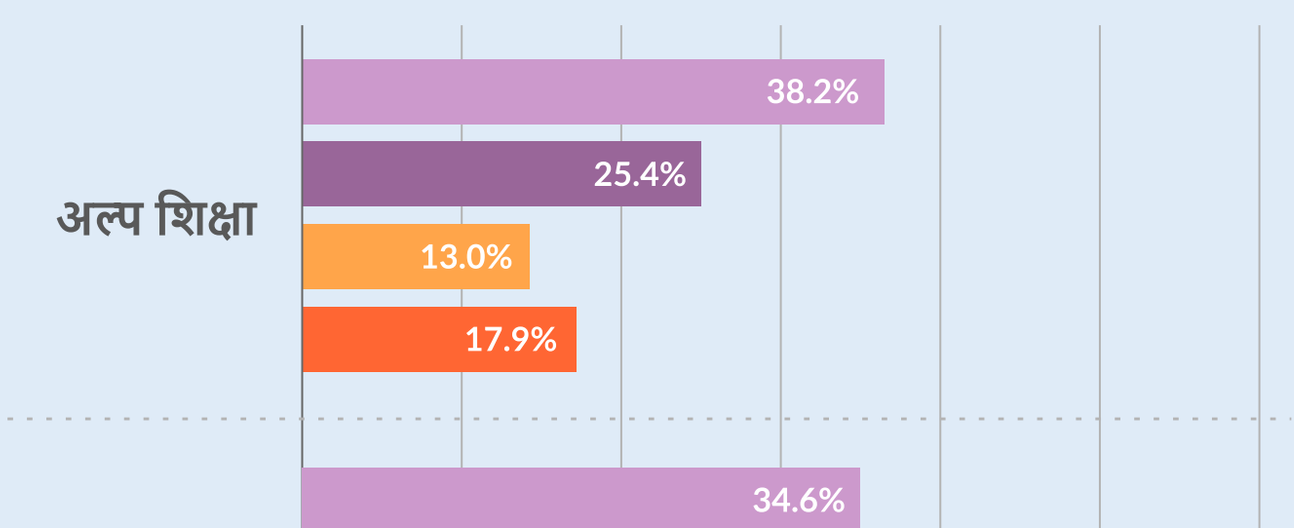

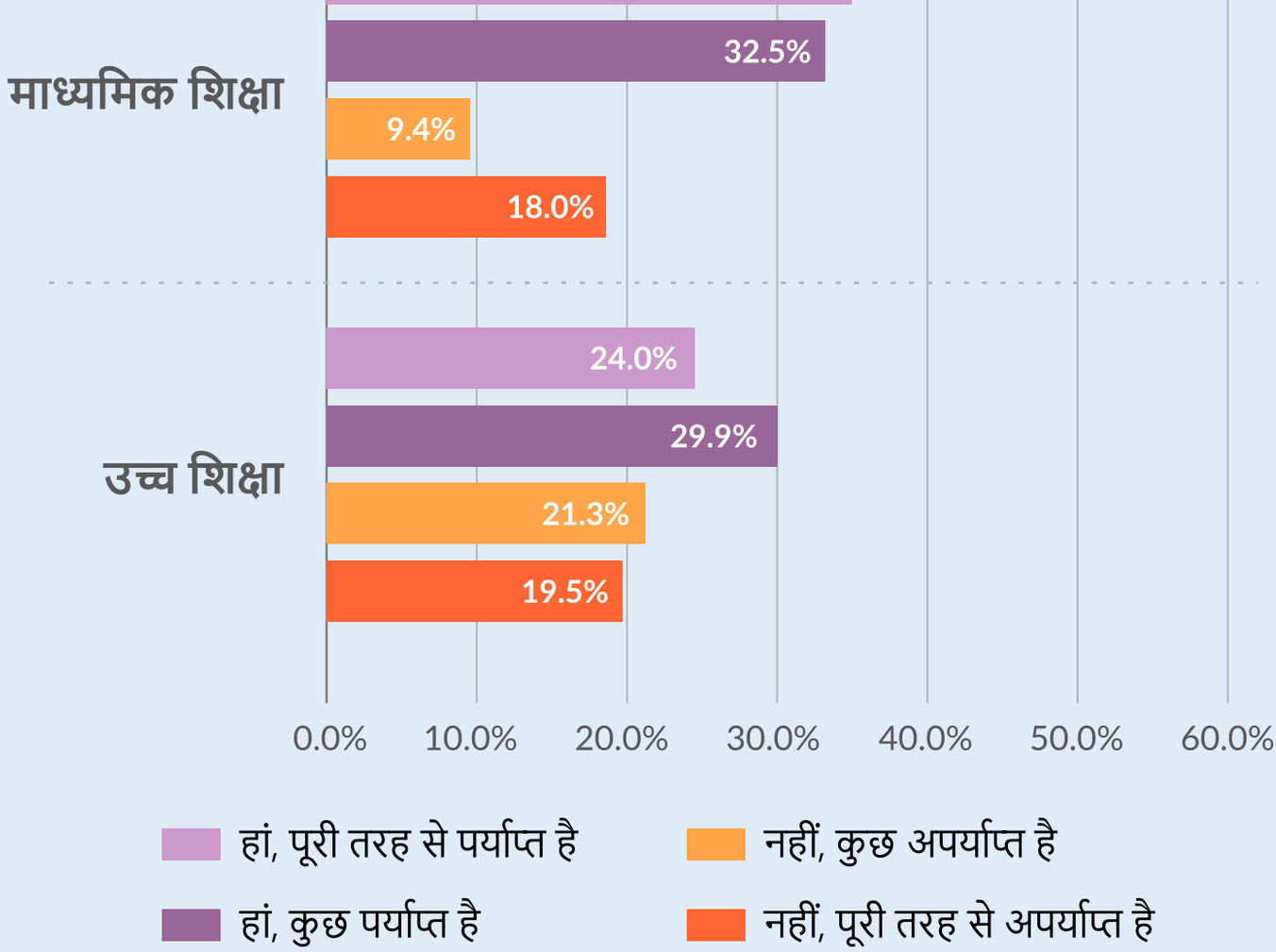

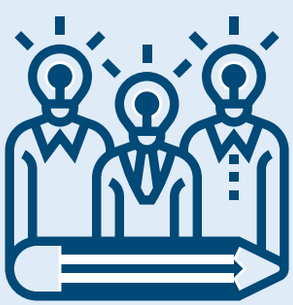

शिक्षा समूहों के बीच, हमने पाया है कि **सरकारी सहायता और राहत के बारे में** सोचने वाले **उत्तरदाताओं के प्रतिशत में शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ** पूरी तरह से पर्याप्त गिरावट है। **उच्च शिक्षा वाले केवल 24% लोग** ही इससे सहमत हैं, **जबकि अल्प शिक्षा वाले 38.2% लोग ऐसा ही सोचते हैं**।

इसी तरह, **उच्च शिक्षा वाले 19.5% लोगों** को लगता है कि **राहत और सहायता पूरी तरह से अपर्याप्त है**, जबकि **अल्प शिक्षा वाले 17.9% लोग ऐसा ही सोचते हैं**।

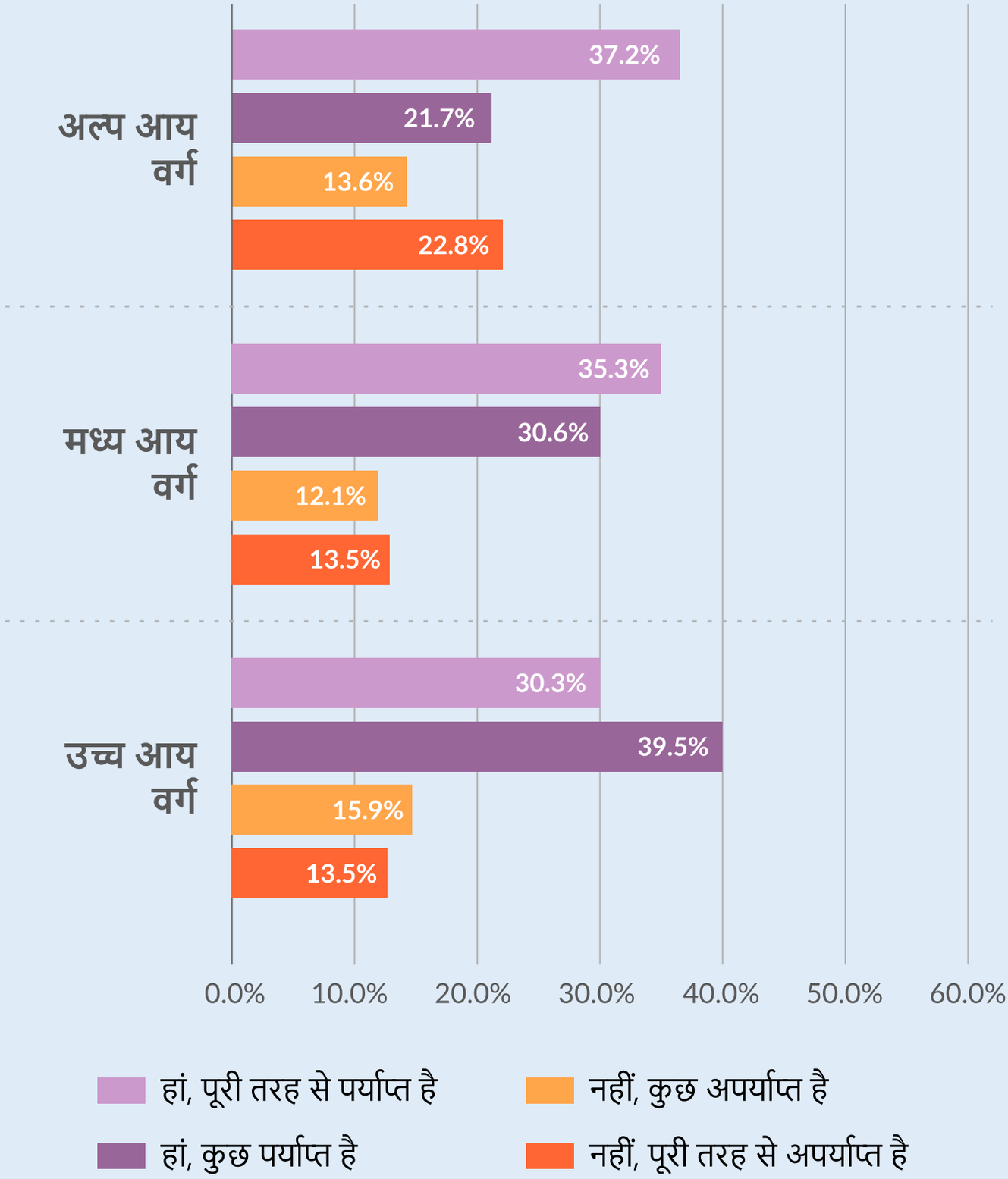

आय समूहों में एक **समान समीकरण देखा गया है,** जिसमें उत्तरदाताओं के **उच्च-आय वाले समूहों का मानना है कि राहत और सहायता पर्याप्त है**, जो **कम आय वाले समूहों (37.2%)** की तुलना में बहुत कम **(30.3%)**।

दिलचस्प बात यह है कि यदि **हम कुल हां और ना के आंकड़े देखते हैं** (कुछ पर्याप्त और पूरी तरह से पर्याप्त संयोजन), तो हमें पता चलता है कि **उच्च आय समूहों में राहत पैकेज (69.8%)** के लिए **उच्चतम अनुमोदन रेटिंग है, जबकि अल्प आय समूहों में सबसे कम है (58.9%)**।

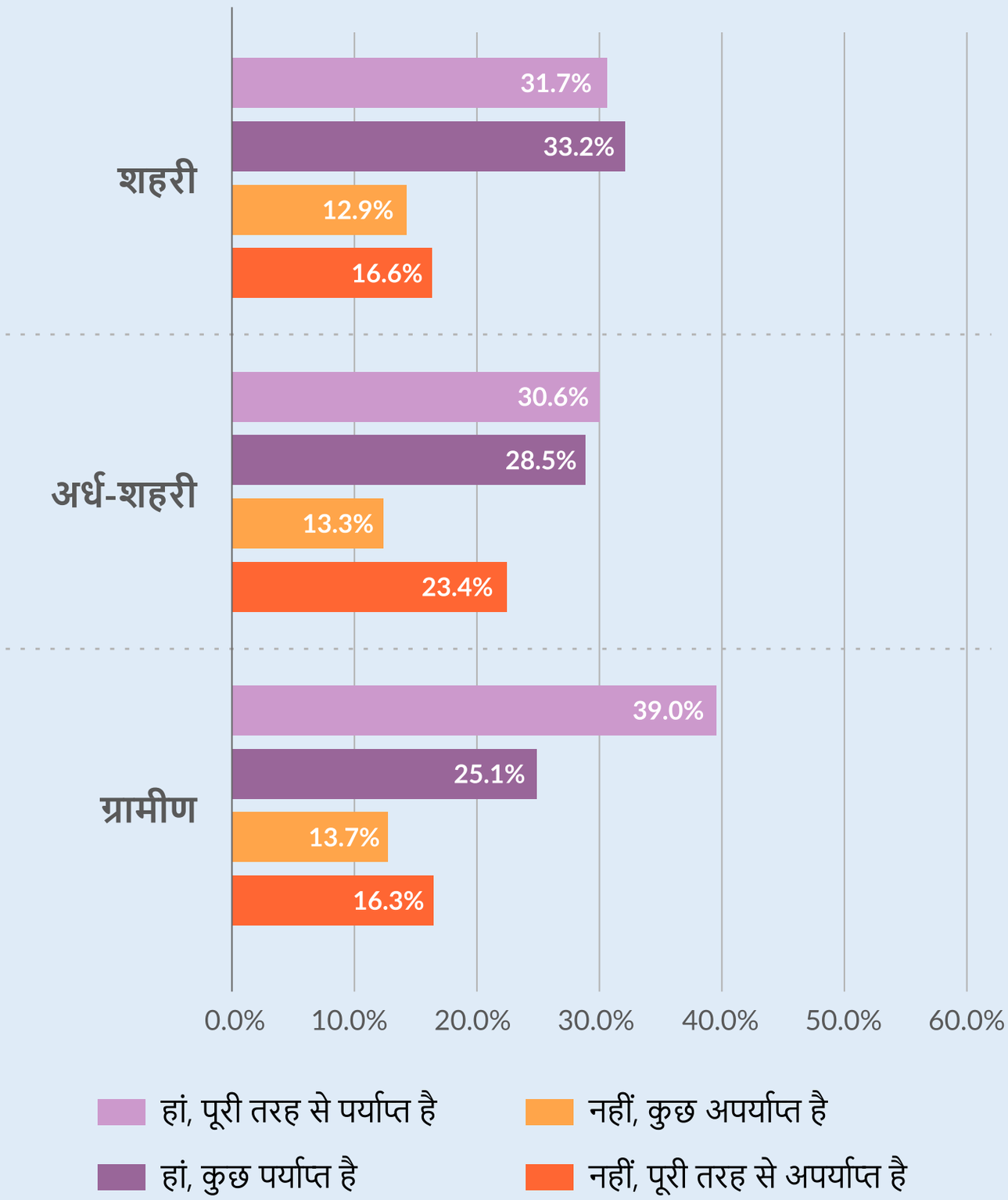

राहत की नीतियों को पर्याप्त मानने वाले ग्रामीण उत्तरदाताओं का प्रतिशत उच्चतम का स्थान है।

39.0%	31.7%	30.6%
शहरी	ग्रामीण	अर्ध-शहरी

हालाँकि, यदि हम कुल **'हाँ' आंकड़ों (कुछ हद तक पर्याप्त और पूरी तरह से पर्याप्त)** को देखें, तो **शहरी और ग्रामीण दोनों उत्तरदाताओं में समान प्रतिशत उत्तरदाताओं (64.9% शहरी और 64.1% ग्रामीण) हैं।**

सभी प्रश्नों में एक "पता नहीं है / यह नहीं कह सकता" विकल्प था जो उत्तरदाता भी चुन सकते थे। यह Q1 के लिए 0.9% और Q2 के लिए 5.5% था। सभी सर्वेक्षण निष्कर्ष और अनुमानो को **टीम C-Voter** की कोरोना ट्रैकर इकोनॉमिक बैटरी तरंग 3 सर्वेक्षण पर आधारित है जो मई 2020 में 18+ वयस्कों के बीच राज्यव्यापी किया गया था, जिसमें हर प्रमुख जनसांख्यिकीय शामिल है।

डेटा को हर राज्य के ज्ञात जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल में शामिल किया जाता है, जिसमें आयु वर्ग, सामाजिक समूह, आय, क्षेत्र, लिंग और शिक्षा स्तर शामिल हैं।
(नमूने का आकार: 1474)

SPRF | सोशल मीडिया पार्टनर

अधिक जानकारी के लिए:
polstrat.com | teamcvoter.com